

“बढ़ते पर्यावरणीय संकट को देखते हुए नीति निर्माता सर्वश्रेष्ठ ईको-प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने से पीछे नहीं हट सकते हैं।”

पिछले साल की एक रिपोर्ट में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 2015 की चेन्नई बाढ़ को ‘मानव निर्मित आपदा’ कहा था, जो यह दर्शाता है कि कैसे झीलों और नदी के बाढ़ के अतिक्रमण ने भारत के छोटे सबसे बड़े शहर को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। चेन्नई की बाढ़ लगातार मानवीय विफलताओं और खराब शहरी डिजाइन का प्रतीक है और ऐसी स्थिति भारत के अधिकांश शहरी केंद्रों के लिए आम बात बनी हुई है। अब, चेन्नई एक और संकट का सामना कर रही है वो है पानी की कमी।

यातायात भीड़ या अपराध जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले मुद्दों के विपरीत, पर्यावरणीय गिरावट एक ऐसी चीज नहीं है, जिसे अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में आसानी से देख या महसूस कर सकें। इसलिए, जब इस तरह की गिरावट के परिणाम कहर बरपाना शुरू करते हैं, तो मानवीय असफलताओं के साथ प्रकृति के प्रतिशोध के बीच संबंध को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। चेन्नई में, पिछली शताब्दी में 30 से अधिक जल स्रोत गायब हो चुके हैं। संकेंद्रण या पक्की सतहों में वृद्धि ने वर्षा के जल को मिट्टी में जाने से रोका है, जिससे भू-जल स्तर में काफी कमी हुई है।

बेहतर दृष्टिकोण के बिना शहरीकरण

हालांकि, चेन्नई, मानव मूर्खता के परिणामों से पीड़ित होने के मामले में अकेला नहीं है। बेंगलुरु महानगर पालिका के उच्च न्यायालय के नोटिस के अनुसार बेंगलुरु में, 15 झीलों ने अपने पारिस्थितिक चरित्र को पांच साल से भी कम समय में खो दिया है, साथ ही शहर की प्रशासनिक संस्था नागरिक सुविधाओं और कुछ बुनियादी सुविधाओं के लिए जिम्मेदार हैं।

झीलों, जो अब अतिक्रमण क्षेत्र बन गया हैं, उसका इस्तेमाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय के रूप में, बस स्टैंड या एक स्टेडियम के निर्माण के रूप में किया जाता है। मैक्सिको शहर में, जो कभी 11वीं और 12वीं शताब्दी में एजटेक साम्राज्य द्वारा निर्मित झीलों का एक नेटवर्क था, ने शहर के केंद्र के लिए रास्ता दिया है। इस वजह से शहर के हिस्से हर साल कुछ मीटर की दूरी पर डूब रहे हैं, जिससे इमारतों को भारी नुकसान होता है।

तेलंगाना में, काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित टैंक और झीलों का बीजान्टिन नेटवर्क वर्षों से गायब हो गया है। हालांकि, सवाल यह नहीं है कि अतीत में हमने क्या क्या मूर्खता की है, बल्कि सवाल यह है कि वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और विशेष रूप से भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। तेलंगाना में, ‘टैंक अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य की जीवन रेखा रहे हैं।’ राज्य के “स्थलाकृति और वर्षा पैटर्न ने टैंक सिंचाई को कृषि उपयोग के लिए जल प्रवाह को संग्रहीत और विनियमित करके एक आदर्श प्रकार की सिंचाई बनाई है।”

तेलंगाना का उदाहरण

हमारे समक्ष ऐसे कई सबक जिनसे हम कुछ सिख सकते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ‘मिशन काकतीय’ के रूप में एक बड़े पैमाने पर कार्याकल्प आंदोलन शुरू किया, जिसमें काकतीय राजवंश द्वारा निर्मित सिंचाई टैंक और झीलों/लघु सिंचाई स्रोतों का पुनः उपयोग शामिल है। अंतर-पीढ़ीगत न्याय के दृष्टिकोण से, यह राज्य में आने वाले पीढ़ियों को पानी का उनको उचित हिस्सा देने और सम्मान का जीवन प्रदान करने की दिशा में एक बेहतर कदम है।

हैदराबाद शहर अब एक स्थायी हाइड्रोलिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है जिसमें देश के कुछ बेहतरीन बुद्धिमान दिमाग काम कर रहे हैं। यह मॉडल एक तरह से पानी के छह स्रोतों को एकीकृत करता है, यहां तक कि शहर के सबसे अविकसित क्षेत्रों में भी जल संसाधनों की न्यायसंगत पहुंच हो सकती है और जिस तरह से भूजल के स्तर को बढ़ाया जा रहा है, उससे मालूम पड़ता है कि ये अपने राज्य में चेन्नई जैसी स्थिति नहीं चाहते हैं।

लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इन निम्नलिखित उदाहरणों से प्रेरणा नहीं ले सकते? जब मैक्सिको शहर अपने डूबते शहरी क्षेत्रों को बचाने के लिए एक नई कार्यकारी स्थिति बना सकता है, बंगलुरु एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निधियों के माध्यम से कुंडलाहल्ली झील (एक बार लैंडफिल) को पुनः प्राप्त कर सकता है और हैदराबाद और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य राजनीतिक इच्छाशक्ति और अच्छी तरह से डिजाइन की गई नीतियों जैसे कि कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से समस्या से उबार सकते हैं, तो ऐसा क्या है जो हमें एक-दूसरे से सीखने से रोक रहा है?

अन्य शहरी केंद्रों को आपदा से बचने के लिए कुछ सर्वोत्तम जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने, रिमॉडेलिंग और कार्यान्वित करने से हमें क्यों पीछे हटना चाहिए? जवाब शायद नीति निर्माताओं द्वारा भविष्य के लिए बनाये जा रहे नीतियों और वे इस समस्या को कितनी गंभीरता से लेते हैं उस पर निर्भर करता है।

2050 तक

ऐसा अनुमान है कि अब से केवल 30 वर्षों में, भारत का आधा हिस्सा शहरों में तब्दील हो जाएगा। यदि हम सही मायने में इस देश के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, तो हम संभवतः अपने आधे लोगों और आने वाली पीढ़ियों के जीवन को कैसे खतरे में डाल सकते हैं, जो बाढ़ से फंसे शहरों में जीने को मजबूर है, बाढ़ के कारण खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं, भूकंप के कारण मर रहे हैं या ताजे पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं? चेन्नई में जो अभी स्थिति है या पिछले साल केरल में आई बाढ़, हमारे लिए खतरे की घंटी है। यदि हम अभी नहीं जागे हैं, तो हमें मानवता पर भारी कहर बरपाते हुए प्रकृति के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हमें अपनी तबाही के लिए परमाणु बमों की आवश्यकता नहीं होगी।

GS World टीम...

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में गोदावरी नदी पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक साथ किया।
- तेलंगाना में स्थापित कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना है।
- दुनिया की इस सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना को मात्र 24 माह में पूरा किया गया है। इस परियोजना के तहत गोदावरी नदी के पानी को पहले ही मेदिगुडा पंप हाउस तक पहुँचाया जा चुका है।
- वर्ष 2000 से तेलुगु राज्यों में बड़े पैमाने पर लिफ्ट परियोजनाएँ शुरू हुईं। इनमें से हंड्री-नीवा, देवडुला, कलवाकुर्थी, नेटटम्पाडु, पट्टिसेमा, पुरुषोत्तमपुरम आदि प्रमुख हैं।

इसके मुख्य बिंदु

- इस परियोजना से तेलंगाना के 13 जिलों की 18 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की जाएगी।
- इसके अलावा राज्य का पेयजल संकट दूर हो सकेगा।
- इसके साथ ही इससे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई जिलों का भी जलसंकट दूर होगा।
- यह परियोजना, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) और भेल के सहयोग से खड़ी हुई है।
- लगभग 82 करोड़ रुपये की मदद से इस परियोजना को तैयार किया गया है।
- तेलंगाना के किसानों की लगातार सूखे के कारण हो रही आत्महत्या से निदान के लिए गोदावरी नदी के पानी को लिफ्ट करने की योजना बनी है।



- इसके लिए सतह से 330 मीटर नीचे 139 मेगावाट की क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन बनाया गया।
- इससे गोदावरी के पानी को पंप के उपयोग से प्रतिदिन 13 टीएमसी पानी को दुनिया की सबसे लंबी 14.09 किलोमीटर की सुरंग के जरिये मेडिगुड्डा बैराज पहुंचाया जाएगा।
- यहाँ से नहरों के जरिए इसे विभिन्न सूखाग्रस्त इलाकों और शहरों को पानी भेजा जाएगा।

- इस परियोजना के तहत 13 जिलों में 145 टीएमसी क्षमता वाले 20 जलाशयों की खुदाई की गई है।
- इस परियोजना के तहत देश में पहली बार 139 मेगावाट क्षमता वाले पंपों का प्रयोग किया जाएगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
 1. यह परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है।
 2. तेलंगाना राज्य में स्थित यह परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है।
 3. इस परियोजना का लाभ तेलंगाना के अलावा आन्ध्र प्रदेश व महाराष्ट्र को भी प्राप्त होगा।
 उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?
 - (a) 1 और 2
 - (b) 2 और 3
 - (c) 1 और 3
 - (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. In the context of Kaleshwaram Lift Irrigation Project, consider the following statements-
 1. This project is situated on godavari river.
 2. The project situated in Telanagna is world's biggest project.
 3. This project will benefit Telangana along with Andhra Pradesh and Maharastra.
 Which of the above statement are correct?
 - (a) 1 and 2
 - (b) 2 and 3
 - (c) 1 and 3
 - (d) All of the above

Expected Questions (Mains Exams)

प्रश्न: देश में बढ़ते शहरीकरण ने पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया है। इस समस्या से निजात पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इको-प्रबंधन प्रथा को अपनाने की आवश्यकता है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए।

(250 शब्द)

Q. The increasing urbanisation in the country has created environmental crisis. For addressing it best eco-managed practice needs to be adopted. Explain with giving the example of Kaleshwaram Lift Irrigation Project.

(250 Words)

नोट : 13 जुलाई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।



Committed To Excellence

